...कैसे 'मनरेगा' मजदूर 'गुझिया' और 'मालपुवा' खाएंगें, दारु 'पीएगें'?

मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी और सामग्री का भुगतान न होने से पसरा प्रधानों, मजदूरों और सामानों की आपूर्ति करने वाले के घरों में सन्नाटा

❖ ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हे एक साल से सामग्री का भुगतान नहीं हुआ ❖ भुगतान न होने से मजदूर कर रहे पलायन, दुकान वाले सामानों की आपूर्ति करने से कर रहे इंकार ❖ अगर मजदूरों का ही भुगतान हो गया होता तो कम से कम गुझिया तो बन जाता ❖ भुगतान न होने का प्रभाव पत्रकारों और बखरा लेने वालों पर भी पड़ा ❖ यह पहली ऐसी होली होगी जब प्रधान गांव में दारु नहीं बांट पाएगें ❖ सरकार ने मनरेगा से जुड़े लोगों को बनाया बेसहारा, ऐसे मोदी, योगी और सांसद के रहने से क्या फायदा जो मजदूरों का भुगतान न करा सकें ❖ बनकटी और कुदरहा में करोड़ों का नहीं लाखों का हुआ भुगतान

बस्ती।...भले ही जिले में वित्तीय साल 23-24 में मनरेगा में धन खर्च करने का रिकार्ड बना हो, लेकिन भारत सरकार ने कई महीनों से मजदूरी का भुगतान न करके एक तरह से मनरेगा श्रमिकों को गांव से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ सरकार 15 दिन में मजदूरी देने की गारंटी देती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार महीनों बाद भी भुगतान नहीं करती।

साल के अंतिम तीन माह श्रमिकों के परिवार को भुगतान न होने से अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सरकार की मजदूरों के पलायन करने के रोकने की मंषा धरी की धरी रह गई। जो मजदूर बचे भी है, वह मजदूरी के अभाव में काम करने से ही इंकार कर दे रहें हैं, एक तरह से ग्राम पंचायतों के विकास का पहिया रुक सा गया है, और इसके लिए मोदी और योगी को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब तो मजदूर, मोदी और योगी को मजदूर विरोधी तक कहने लगें हैं। मजदूरी का भुगतान न होने का प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिस मोदी और योगी का मजदूर जय-जयकार करते थे, आज उसे वह मजदूर विरोधी बताकर श्रमिकों के परिवार को आर्थिक संकट में डालने और रोजगार छीनने वाला बता रहें हैं। अधिकांष मजदूर सवाल कर रहे हैं, कि ऐसे मोदी, योगी और सांसद के रहने से क्या फायदा जो मजदूरों का भुगतान न करा सके। चुनाव के समय भुगतान न करके मोदी और योगी, मजदूरों के निषाने पर आ गएं और इसे बहुत बड़ा नुकसान होने का रिस्क लेना बता रहें है।

जिले के लगभग तीन लाख मनरेगा श्रमिकों का परिवार मनरेगा से मिलने वाले मजदूरी से ही चलता है। सवाल उठ रहा है, कि अगर सरकार के पास मजदूरी देने तक पैसा नहीं हैं, तो फिर योजना को चलाने से क्या लाभ? वैसे भी इस योजना को लेकर सरकार का जो रवैंया पिछले दिनों भुगतान को लेकर रहा है, उससे तो यही लगता है, कि सरकार इस योजना को चलाना ही नहीं चाहती, और धीरे-धीरे इस योजना को बंद करना चाहती है। सवाल यह भी उठ रहा है, कि उन मजदूरों और साम्रगी की आपूर्ति करने वालों की क्या गलती, जिन्होंने काम किया और आपूर्ति की। क्यों सरकार इन लोगों को सजा दे रही है? पहली अप्रैल से जो नियम कानून लागू होने जा रहा हैं, उसमें मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने की गुजाइंष बहुत कम रह जाएगी। बहरहाल, सरकार ने मजदूरी का भुगतान न करके एक तरह से श्रमिकों के परिवार को सड़क पर ला दिया। अनेक प्रधानों का भी यह कहना है, कि सरकार अगर सिर्फ मजदूरी का ही भुगतान कर देती तो मजदूर खुषी-खुशी मोदी को वोट करते, कहते हैं, कि कम से कम मजदूरों का परिवार होली में गुझिया और मालपुवा तो खा लेता।

प्रधान के पास भी पैसा नहीं रहा कि वह होली पर दारु पिलाए। मगर, सरकार ने तो मजदूरों का गुझिया और मालपुवा तक को छीन लिया। मजदूरी के इंतजार में न जाने कितने श्रमिक कर्जदार हो गए, हालत यह हो गई हैं, कि अब तो गांव का बनिया भी उधार देने से मना कर रहा है। जो प्रधान ऐसे कठिन समय में श्रमिकों की मदद करते थे, वे भी इस स्थित में नहीं रहे, कि सौ-पांच सौ रुपये की मदद कर सके। क्यों कि प्रधान और उनका परिवार भी इस योजना से जुड़ा हुआ है। सिर्फ प्रधान और मजदूरों का परिवार इस योजना के लाभ से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, बीडीओ, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष सहित विकास भवन के अधिकारी भी जुड़े है।

वे लोग भी भुगतान न होने से प्रभावित हो रहें है। भले ही चाहें इन पर होली त्यौहार का कोई फर्क न पड़े, लेकिन जिन लोगों की सुबह ही बखरे से होती थी, उन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनके सामग्री का भुगतान एक साल बाद भी नहीं हुआ। प्रधानों के पास अब न तो पैसा रह गया है, और सामानों की आपूर्ति करने वाले दुकानदार ही उन्हें उधार में सामान देने को तैयार है। उधार के चलते इन लोगों की दुकाने जक टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। एक-एक ग्राम पंचायतों की देनदारी लाखों में हैं, किसी का बीस लाख है, तो किसी का 30 लाख। भुगतान न होने का प्रभाव आपूर्तिकर्त्ता के बिजनेस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका प्रभाव अखबार वालों और पत्रकारों पर भी पड़ा है। जो प्रधान होली के अवसर पर विज्ञापन और मिठाई के नाम पैसा देते थे, उन्होंने ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक प्रधान ने बताया कि अधिकतर प्रधान अब पक्के कार्यो की स्वीकृति के लिए परेषान नहीं रहता, क्यों कि साहबों को एडवांस में बखरा चाहिए, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि भुगतान होगा कि नहीं, इन्हें तो सिर्फ बखरे से ही मतलब रहता है। यह भी सही है, कि 15 मार्च को बनकटी और कुदरहा में करोड़ों का नहीं बल्कि लाखों में भुगतान हुआ, बताया गया कि बनकटी में लगभग 30 लाख और कुदरहा में लगभग 13-14 लाख का ही भुगतान हुआ।

कई प्रधानों का कहना है, कि अगर भुगतान और मनरेगा योजना के मामले में सरकार का इसी तरह का रवैंया रहा तो ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया रुक जाएगा, और इसके लिए और कोई नहीं बल्कि सरकार ही जिम्मेदार होगी। सरकार अगर इस योजना को लेकर इतनी ही सजग होती तो यह पत्र न जारी करती कि 22-23 के बकाए को जो भुगतान 23-24 में हुआ, उसे भी 23-24 का माना जाएगा, और उसी के अनुसार 60-40 का अनुपात मेनटेन होगा। इस आदेष के चलते जिले के नहीं बल्कि प्रदेष की न जाने कितनी ग्राम पंचायतें भुगतान पाने से वंचित रह गई। इसी लिए बार-बार कहा जा रहा है, कि जिस योजना की नकल करके पूरे विष्व में लागू हुआ, उसी योजना को सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। यह न सिर्फ मजदूरों के साथ बल्कि पूरे देष के साथ धोखा होगा।

'होलसेलर' रिटेल का 'काम' नहीं कर 'सकता': शीतल

बैठक का शुभारंभ प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल के वर्चुअल संबोधन से हुआ

तेजयुग न्यूज

बस्ती। बस्ती केमिस्टस एंड ड्रिगस्ट्स एसोसिएशन के जिले के थोक दवा व्यवसाईयों की बैठक बीसीडीए के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने किया। बैठक का शुभारंभ प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल के वर्चुअल संबोधन से हुआ। कहा कि जिले के किसी भी सदस्य को यदि किसी भी कंपनी से कोई समस्या हो तो वह अपनी समस्या के समाधान के लिए जिला इकाई के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकता है।

उसकी समस्या के समाधान के लिए त्वरित एवं सुसंगत प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तृत विवरण देते हुए प्रदेश महामंत्री ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर से प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर संतोषजनक वार्ता हुई है। ट्रेड से संबंधित कई समस्याओं का समाधान भी हुआ है। उन्होंने मजबूत जिला इकाई बस्ती के मजबूत नेतृत्व एवं संगठित सदस्यों की भूरि भूरि प्रशंसा किया।

मुख्य एजेंडा थोक दवा व्यवसाईयों के व्यवसाय में आने वाली समस्याओं पर 'चर्चा की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि मार्च क्लोजिंग की समस्या पर विस्तृत चर्चा के बाद तय हुआ कि अध्यक्ष, महामंत्री, होलसेल कमेटी अध्यक्ष, सदस्य जय गोपाल गुप्ता एवं शक्ति गुप्ता की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। जिस किसी भी सदस्य का पैसा रुका हुआ है, वह संपूर्ण विवरण के साथ कमेटी को अवगत करा दें, कमेटी दूसरी पार्टी से वार्ता कर भुगतान में आने वाली समस्या का निराकरण कराते हुए भुगतान को सुनिश्चित करायेगी। अगर किसी पार्टी के यहां कई व्यवसाईयों का पैसा फंसा हुआ है तो संगठन उसके विरुद्ध कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगा।

अध्यक्ष ने लोगों को आश्वस्त किया कि कलवारी सेक्टर की पार्टी शीतल मेडिकल स्टोर जिसने कई सदस्यों का ज्यादा पैसे का भुगतान रोक रखा है, उससे लोगों का पैसा दिलवाया जाएगा। विवादित प्रकरण को 45 दिन के बाद कमेटी को सौंप दिया जाएगा जिस पर कमेटी उचित निर्णय लेकर के कार्यवाही करेगी। होलसेलर्स द्वारा रिटेलर्स को दिए जाने वाले प्रतिशत पर सहमति न बन पाने के कारण समस्या के निराकरण के लिए कमेटी को अधिकृत किया गया। चुनाव के समय थोक दवा व्यवसाईयों के द्वारा कैश कलेक्शन को ले जाने में प्रशासन के तरफ से जो समस्या आती है उसके समाधान के लिए अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि प्रशासन से मिलकर प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या ना आने पाए। लीकेज, ब्रेकेज एवं एक्सपायरी पर हुई चर्चा पर सहमति बनी की सभी रिटेलर्स महीने की सात से लगायत 15 तारीख के बीच तीन महीने तक की अपनी एक्सपायर दवाओं को निश्चित प्रोफार्मा पर भरकर रिसीविंग ले ले। उनके क्लेम का सेटलमेंट समय पर कर दिया जाएगा। समय-समय पर एलओटी पर सदस्यों द्वारा किए गए शत प्रतिशत योगदान के लिए अध्यक्ष ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया। होलसेल कमेटी अध्यक्ष शीतला पटेल ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर कोई भी होलसेलर रिटेल का काम नहीं कर सकता, अगर कोई होलसेलर रिटेल का काम करता है तो वह इस काम को न करें। क्यों कि आपके द्वारा ऐसा करने पर समाज मे दवा व्यवसाय के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है। व्यवसाय का मजा तभी है जब आप अपने अधिकार क्षेत्र एवं आहार क्षेत्र में रह करके काम करें, जिसका जो हक है उसको वह मिलने दीजिए।

महामंत्री अशोक कुमार सिंह ने कहा की अभी तक आप थोक दवा व्यवसाय में व्यवसायियों को आने वाली समस्या पर चर्चा कर रहे थे, कहा कि दवा व्यवसाईयों के व्यवसाय से समाज में आने वाली समस्या पर भी चर्चा करें। नारकोटिक्स दवाइयां की बिक्री की तरफ सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रशासन नारकोटिक्स दवाइयां पर काफी सख्त है। प्रशासन सख्त हो या ना हो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्राहक को पहचान कर दवा दें इस चीज को जरूर देखें की वह दवा को सिर्फ दवा के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा है या नशे के लिए ले जा रहा है। होलसेल पॉइंट पर या रिटेल पॉइंट पर जहां से भी जिस किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई कमी पकड़ में आती है तो हम सभी का दायित्व है कि इसको उसी पॉइंट पर रोके।

व्यक्ति 'बाधित' और 'नष्ट' हो 'सकता', पर विचारधारा 'नहीं'!

लोकतंत्र को कुचलने के विषय को लेकर हुई परिचर्चा

तेजयुग न्यूज

बस्ती। लोकतंत्र को कुचलने की साजिष को लेकर एक परिचर्चा हुई, जिसमें युवाओं ने खुलकर अपनी बाते रखी, और कहा कि इतिहास गवाह है, कि बड़े से बड़ा तानाषाह पूरी तरह विपक्ष को समाप्त नहीं कर पाया। जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया, वही समाप्त हो गया। कहा भी जाता है, कि जिस देष में विपक्ष कमजोर होता है, उस देष का मुखिया तानाषाह हो जाता। लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, एक मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरुरी हैं, जितना मानव को सांस लेने के लिए हवा।

आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं,उसकी सोच उसकी विचारधारा को नहीं

अनेक लोगों ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों को फांसी दी पर उनकी सोच को कभी फांसी के तख्ते पर लटका कर भी खत्म नहीं कर सके। कहा कि व्यक्ति बाधित हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा न तो बाधित होती है, और न नष्ट ही। अतीत हमें यह बताता है कि जब-जब सत्ता क्रूर हुई, धड़-पकड़ जोरों से शुरू हुआ, दमनकारी रवैंया अपनाया। यही अनुचित एक्शन सत्ताधारी के पतन का कारण बनता है, और परिवर्तन भी होता है। किसी को गिरफ्तारी से घबराने की जरूरत तो कतई नहीं, क्योंकि बदलाव का अध्याय लिखा जाना शुरू हो चुका है। कहा गया कि कोई भी राजनीति पूर्णतः अच्छी या बुरी नहीं होती। अच्छाई और बुराई दो ऐसे धागे हैं, जो सारे इतिहास में फैले हुए हैं। लोग जो कुछ भी करते हैं, उसका उपयोग अच्छाई और बुराई दोनों के लिए करते है। यह अच्छाई और बुराई काले और सफेद धागे की तरह आपस में इस तरह घुले मिले होते हैं कि उसे एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं। युवकों ने जोर देकर कहा कि क्या सत्ता को जरा भी भरोसा नहीं अपने वोटरों पर नहीं जो इस तरह से विपक्ष का सफाया करने में तुली हुई है।

क्या सत्ता के सांसद, विधायक, मंत्री भ्रष्टाचार के कलंक से अछूते हैं। मोदी ने 2014 में कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि सत्ता के लोग खाएं या निगले उनको पूरी छूट रहेगी। सत्ता पाने और पावर में आने के बाद सबसे अधिक भ्रष्टाचार सांसद, विधायक और मंत्री एवं इनके लोग ही करते हैं। कहते हैं, कि यह लोकतंत्र है, या डर, खौफ तंत्र जो ईडी, सीबीआई से चल रहा है। सब जोड़कर इसे तानाशाही कहा जा सकता है जनता काफी शिक्षित हो चुकी है। भारत में सबसे अधिक युवा मतदाता हैं। मीडिया पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि मीडिया भले सत्ता की साथी और दासी हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया सब दिखा रहा है और हकीकत बयां कर रहा है अब हर हाथ में स्मार्ट फोन है जो तानाशाही को दिखा भी रहा है उजागर भी कर रहा है। कहा गया कि रेल बिका, तेल बिके, बिके हवाई अड्डे, महंगाई की मार पड़ी है, बंद हो चुके रोजगार और धंधे।

पांच किलो का लालच देकर चल रहे राजनीति के धंधे। जनता खूब विश्लेषण कर रही तानाशाही का दमन होगा और जनाक्रोश की लावा जब फूटती है, तो इसका परिणाम भयावाह होता है। युवाओं ने कहा कि ऐसी तानाशाही नहीं देखी। परिचर्चा में यशवंत सिंह रोलू, राजन, धर्मेंद्र सिंह, रोहित शर्मा, शिवकुमार यादव, शिव लखन मौर्य, रंजन आदित्य चैधरी, राजकिशोर, केसरी यादव, शिवम, लालजी, दुर्गेश, शंभु गुप्त, कमलेश पटेल, जयराम पंडित, जवाहरलाल कन्नौजिया, तुलसी राम सोनकर और दीपू सहित अन्य ने भाग लिया।

दो ट्रकों में भिड़ंत लगी आग खलासी की मौत

तेजयुग न्यूज

ऊंचाहार/रायबरेली : कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर मदारीगंज स्थित जामो गैस एजेंसी के पास दो ट्रकों की भिड़ंत में आग लग गई, घटना से खलासी की जलकर मौत हो गई, जबकि चालक सड़क पर कूदकर घायल हो गया, जिसे सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है।

जगतपुर थाना क्षेत्र के जोगमगदीपुर गाँव निवासी उमानाथ ट्रक चालक है, जो शनिवार की भोर में अपने साथ खलासी पिंटू 40 वर्ष निवासी कोरांव जिला प्रयागराज को लेकर ट्रक से प्रयागराज की तरफ जा रहा था, ट्रक खलासी चला रहा था ,तभी सामने से आ रहे क्लिंकर लदे ट्रक से ट्रक की टक्कर हो गई, टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के इंजन में आग लग गई, चालक उमानाथ सड़क पर कूदकर घायल हो गया, जबकि खलासी फंस गया, जिसकी जलकर मौके पर ही मौत हो गई,मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई।कोतवाल अनिल कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।जिसके बाद शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है,जबकि घायल चालक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक में आग लगने पर वजह से खलासी की जलकर मौत हो गई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है।

'पैरावेट' के सामने 'आर्थिक' संकट, 'चूल्हा' जलना 'मुस्किल'

बनकटी/बस्ती। विकास खंड मुख्यालय से सटा राजकीय पशु चिकित्सालय में पैरावेटों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया हैं, इनके घरों में चूल्हा जलना मुस्किल हो रहा है। परिवार के सामने होली का त्यौहार मनाना कठिन हो गया है। कारण, इन लोगोंका पारिश्रमिक न मिलना। गोकुल मिशन का अभी चैथे वर्ष का भुगतान न होना 2019-20 का टीकाकरण, टैगिंग, लंपी डिजीज आदि का भुगतान आज तक नहीं हुआ। पैरावेट अशोक तिवारी, राजेश शुक्ल, पवन यादव, वशिष्ठ पान्डेय, कुलदीप यादव आदि ने बताया कि उपरोक्त का भुगतान न होने से त्योहार फीका पड़ रहा है। अधिकारियों से जल्दी भुगतान करने का आग्रह किया है। इस सम्बन्ध में डा रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि इन लोगों की समस्या हमारे स्तर का नहीं है। इसके लिए शनि शुक्ला से बात करिए। इस सन्दर्भ में जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ अमर सिंह ने बताया कि अभी तक यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। होली की छुट्टी खत्म होने के बाद जिस दिन आफिस खुलेगा उसी दिन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पेमेंट कराने का पूरा-पूरा कोशिश करूंगा।

'रुधौली' के 'बीईओ' पर लगा 'बखरा' मांगने का 'आरोप'

महिलाओं को भेजने वाले नोटिस को यह प्रेम पत्र का नाम देते

तेजयुग न्यूज

बस्ती।...जब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ही खुले आम कम्पोजिट ग्रांट में बखरा मांगने लगेगें तो हो चुका शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। जिस तरह रूधौली के खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कमीषन को लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकों ने जमकर नारेबाजी की और एक दिवसीय कार्यशाला का बहिष्कार किया, उससे पता चलता है, कि इस विभाग में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है।

कार्यशाला का आयोजन की अव्यवस्था को देखते हुए अध्यापकों ने बहिष्कार करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी पर तरह-तरह के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शिवरतन समेत अन्य सभी अध्यापकों ने बताया कि कार्यशाला को प्रातः 9.30 पर बुलाकर 11.00 बजे तक कोई बैठने की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे नाराज होकर कई विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समय से आने के बावजूद भी वापस चले गए। लोगों ने बताया कि पहली बात अव्यवस्था दूसरी बात 12 बजे के बाद आकार खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने पहुंचकर लोगों की उपस्थिति लेने और अभद्र भाषा में बात किया। जिससे अध्यापकों ने नाराजगी जताई। इसके बाद

कार्यालय के सामने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापकों ने जमकर नारेबाजी की जिसमें कहा गया कि बीइओ तेरी तानाशाही नही चलेगी, नही चलेगी, अध्यापकों का शोषण बंद करो बंद करो, महिला अध्यापकों से अभद्रता नही चलेगी, नही चलेगी, आदि नारे बाजी की गई। ब्लॉक अध्यक्ष शिव रतन ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने पत्राचार के माध्यम से कार्यशाला में 9.30 पर आयोजन करने के बावजूद 11.30 तक अध्यापकों को बैठने तक कई व्यवस्था न किया जाना निंदनीय है।

इसके अलावा भी कंपोजिट विद्यालय में ग्रांट योजना के तहत विकास हेतु धन वितरण होता है उसमें भी फाइल पास करने के अन्य बहाने से पैसा लेने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ यदि किसी मामले को लेकर नोटिस भेजा जाता है तो उसे भी प्रेम पत्र कहकर भी लोगो का मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में कार्यरत अनुचरों को कार्यालय से अटैच करने व उन्ही से धनउगाही कराने का आरोप लगाया है। इस मौके पर राम भवन यादव, हरि गोपाल शुक्ल, मंजरी सिंह,निहारिका जायसवाल, आकांक्षा वर्मा, प्रीति ओझा,पुष्पा वर्मा,पूजा चैधरी,कंचनलता, अनुराधा, सोनी सोनवानी, राम प्रसाद गुप्ता, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार शर्मा, अरविंद चैधरी, जयप्रकाश, सदानंद, वेद प्रकाश, शैलेंद्र, अशोक, मंजू देवी सहित सैकड़ो अध्यापकगण मौजूद रहे।

जब इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार से वार्ता की गई तो सारे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब अध्यापक की उपस्थिति ली गई उसी से उनको नाराजगी हो गई और कंपोजिट ग्रांट से मिलने वाले लाभ को कौन कितना कमीशन दिया वो भी साक्ष्य मागने की बात कही है।